



2026:AHC: 57908

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 6827 वर्ष 2026

आलोक कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अभय कुमार शुक्ला, संजय मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान 528 बी.एन.एस.एस. आवेदन शिकायत वाद संख्या 35835 वर्ष 2024 (कमलेश कुमार शर्मा बनाम आलोक कुमार) की पूरी कार्यवाही, साथ ही एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत विवादित समन आदेश दिनांक 23.01.2025, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद की न्यायालय में लंबित है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि पक्षों के बीच पैसे का विवाद है और विपक्षी संख्या 2 ने आवेदक के खिलाफ एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि पैसे के भुगतान के संबंध में कुछ विवाद है, इसलिए समझौते के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की अच्छी संभावना है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय शीर्ष अदालत के दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबाल एच., 2010 (5) एस.सी.सी. 663 के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत हैं:—

"17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, 'सम थॉट्स टुवर्ड्स लॉ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रिफॉर्म्स ऑन द टॉपिक ऑफ सेक्शन 138, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट—टैकलिंग एन एवलांच ऑफ केसेज' (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पृष्ठ 5 पर।

"...अपराध के अन्य रूपों के विपरीत, यहाँ दंड (जहाँ तक शिकायतकर्ता का संबंध है) प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि धन का भुगतान सुनिश्चित करने का अधिक साधन है। शिकायतकर्ता का हित चेक के लेखक को जेल में देखने के बजाय मुख्य रूप से पैसा वसूलने में निहित है। जेल की धमकी केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। उस अभियुक्त के खिलाफ जो जेल की सजा काटने को तैयार है, चेक धारक के लिए उपाय के रूप में बहुत कम उपलब्ध है।

यदि हम एक तरफ अंतिम निर्णय से पहले 'समझौता' या 'निस्तारित' की गई शिकायतों की संख्या और दूसरी तरफ उन मामलों की जांच करें जिनमें निर्णय और दोषसिद्धि हुई, तो हम पाएंगे कि बड़ा हिस्सा सुलझा लिया गया था और केवल बहुत कम संख्या में मामले जारी रहे। "

18. यह काफी स्पष्ट है कि चेक बाउंस होने के अपराध के संबंध में, उपचार के प्रतिपूरक पहलू को दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान महान्यायवादी द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को कुछ समर्थन भी मिलता है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामलों में वास्तव में शमन के माध्यम से समझौता या निपटारा किया जा रहा है, हालांकि मुकदमेबाजी के बाद के चरणों के दौरान, जिससे न्याय वितरण में अनुचित देरी होती है। यहाँ समस्या मुकदमेबाजों की अपने विवाद को सुलझाने के साधन के रूप में देरी से शमन को चुनने की प्रवृत्ति के साथ है।

19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान महान्यायवादी का तर्क यह है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पक्षकार मजिस्ट्रेटों द्वारा शिकायतों पर संज्ञान लेते ही इसे चुनने के बजाय अंतिम उपाय के रूप में शमन को चुन रहे हैं। इस तरह के व्यवहार का एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका लेने के इच्छुक हैं और फिर निपटान का रास्ता तभी चुनते हैं जब कोई अन्य रास्ता नहीं बचता। जबकि इस तरह के व्यवहार को मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से तर्कसंगत माना जा सकता है, लेकिन कठोर तथ्य यह है कि शमन चुनने में अनुचित देरी विभिन्न स्तरों पर अदालतों के समक्ष लंबित बकाया मामलों में योगदान देती है। यदि अभियुक्त मुकदमेबाजी के बाद के चरण में अपराध के शमन के माध्यम से निपटान या समझौता करने को तैयार है, तो यह आम तौर पर शिकायतकर्ता के मामले में कुछ योग्यता का संकेत देता है। ऐसे मामलों में



यह वांछनीय होगा कि पक्षकार मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों के दौरान शमन चुनें। हालाँकि, यदि अभियुक्त के पास अन्य आधारों के अलावा गलती, जालसाजी या जबरदस्ती जैसा कोई वैध बचाव है, तो मामले को निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से लड़ा जा सकता है।"

5. अधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, यह निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त आज से एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हो सकता है और समझौते के माध्यम से अपराध के शमन की मांग करते हुए आवेदन दे सकता है तथा चेक राशि का 10% जमा कर सकता है। ऐसा आवेदन दिए जाने पर संबंधित न्यायालय इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कदम उठा सकता है और अभियुक्त को इस दिशा में प्रयास करने के लिए और अवसर प्रदान करेगा जो आज से अधिकतम चार महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। इसके पश्चात, न्यायालय आज से पांच महीने की अवधि के भीतर विशेष रूप से **दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त)** के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आदेश पारित करेगा।

6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के शमन के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होने और मुकदमे का सामना करने की आवश्यकता है और न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध कानून के अनुसार आगे बढ़ने और कानून द्वारा अनुमत उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम और उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपर्युक्त पांच महीने की अवधि में या आवेदन के आलोक में दिए गए निर्णय तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के विरुद्ध कोई दंडात्मक उपाय नहीं अपनाया जाएगा।

8. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उस अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से इस न्यायालय में यह आवेदन दिया गया है।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह आवेदन **निस्तारित** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

19 मार्च, 2026

मिनी